

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2015/श्रावण 8, 1937	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 74
No. 98]	DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2015/SRAVANA 8, 1937	[N.C.T.D. No. 74

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2015

सं. फा. 12 (2)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/594.— दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 22 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 12(6)/वित्त(टी एंड ई)/2008-2009/जेएसवित्त/248 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाये जाने के लिये की गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि होटलों के स्वामी की प्राप्ति के कुल बिक्री पर वसूल किये जाने वाले कर की दर दिनांक 01 अगस्त, 2015 से पन्द्रह प्रतिशत होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उपसचिव—VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2015

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2015-16/ds-vi/594.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) and in supersession of this Government's Notification No.F.12(6)/Fin(T&E)/2008-2009/jsfin/248 dated the 22nd June, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies

that the rate of tax to be levied on the turnover of receipt of a proprietor of hotels shall be fifteen per cent w.e.f. 1st August, 2015.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A.K.SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह पुलिस (II)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2015

सं.फा.11/79/2013/गृह पुलिस-II-6651.- अपराधिक अपील सं. 193/2006 राज्य बनाम मनु शर्मा एवं अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.5.2013 के निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली में साक्षियों की सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए साक्षियों की सुरक्षा के लिए निम्न योजना बनाते हैं :

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (क) यह योजना "दिल्ली साक्षी सुरक्षा योजना, 2015" के नाम से जानी जाएगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत) तक किया जाएगा।
- (ग) यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं :-

- (क) "संहिता" का अर्थ अपराधिक प्रक्रिया 1973 (1974 का 2) की संहिता से है;
- (ख) "साक्षी की पहचान को छुपाना" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है साक्षियों के नाम, पता तथा अन्य विवरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर करने या प्रकाशित न करने की शर्त, जिससे साक्षियों की पहचान हो सके;
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष ड्यूटी पर सदस्य सचिव/अधिकारी जो अकेले इस योजना के अंतर्गत साक्षियों की सुरक्षा के लिए पारित कर सकते हैं और साक्षियों के पहचान की सुरक्षा/पहचान में परिवर्तन/साक्षियों का पुनर्वास, धमकी का श्रेणीकरण/स्वरूप, अवधि तथा खंड 7 के विवरण के अनुसार सुरक्षा के प्रकार से है;
- (घ) "परिवार के सदस्य" में अभिभावक, पति-पत्नी, भाई-बहन, बच्चे, गवाह के पोता-पोती, नाती/नातीन आते हैं;
- (ङ) "फार्म" का अर्थ इस योजना के साथ संलग्न "साक्षी सुरक्षा आवेदन फार्म" से है;
- (च) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;
- (छ) "इन कैमरा कार्यवाही" का अर्थ है जहां जनता और प्रेस को जाने की अनुमति न हो;
- (ज) "लाइव लिंक" का अर्थ है और इसमें कोई लाइव टेलीविजन लिंक या ऐसी अन्य व्यवस्था सम्मिलित है, जिसके द्वारा कोई साक्षी जब कोर्ट रूम से अनुपस्थित रहता है, तो मुद्दे पर बयान दे सकता है;
- (झ) "सुरक्षा उपाय" का अर्थ है साक्ष्य के दौरान साक्ष्य लेते समय न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही से सुनिश्चित करना कि साक्षी स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के जीवन या प्रतिष्ठा या सम्पत्ति के लिये डॉट-डपट या भय से मुक्त होकर प्रमाण दे सके, ऐसे उपायों में शामिल होंगे, लेकिन वीडियोकांफ्रेंसिंग, साक्षी और दोषी के बीच आमना-सामना रोकने तथा किसी साक्षी की पहचान के विवरण को रोकने तक सीमित नहीं हैं;
- (ञ) "गंभीर अपराध" का अर्थ है ऐसे अपराध जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या कम से कम सात वर्षों के कारावास का प्रावधान हो;
- (ट) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का अर्थ दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 6 में वर्णित है;
- (ठ) "धमकी विश्लेषण रिपोर्ट" का अर्थ पुलिस के अपर आयुक्त/पुलिस के उपायुक्त/जिला के पुलिस अपर उपायुक्त/मामले की जांच करने वाली यूनिट एजेंसी द्वारा मामले की गंभीरता तथा साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों को मिली धमकी की आशंका की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना। इसमें साक्षी या उसके परिवार के जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के बारे में प्राप्त धमकी की प्रकृति का विशेष उल्लेख होगा जोकि धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के उद्देश्य, कारण तथा धमकियों को अमल में लाने के उपायों का विस्तृत विवरण अलग से होगा।
मामले के संबंध में साक्षी की सुरक्षा हेतु उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों पर सलाह देने के अलावा यह धमकी के बोध का भी श्रेणीकरण करेगा।

- (ड) "साक्षी" का अर्थ है कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के बारे में सूचना या दस्तावेज़ रखता है, जिसका किसी अपराधिक कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान लिया जाता है और जिसने कोई बयान दिया है या जिसने ऐसी कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य दिया है या देने हेतु सहमति दी है;
- (ढ) "साक्षी सुरक्षा आवेदन" का अर्थ है साक्षी सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित फार्म पर आवेदन प्रस्तुत करना। यह साक्षी, उसके परिवार के सदस्य या उसके विधिवत् किये गए वकील या संबंधित जांच अधिकारी/स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और यह संबंधित अभियोजक के माध्यम से अग्रेषित किया जाना उचित होगा;
- (ण) "साक्षी सुरक्षा निधि" का अर्थ इस योजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए साक्षी सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए व्यय के लिए सृजित की गई निधि से है;
- (त) "साक्षी सुरक्षा आदेश" का अर्थ है गवाहों या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के बारे में मिली धमकी से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विवरण संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से है, इसमें साक्षी सुरक्षा आवेदन की अनिर्णीत अवधि के दौरान यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं तो वे भी सम्मिलित हों;
- (थ) "साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ" का अर्थ, दिल्ली पुलिस का समर्पित सेल जिसके पास साक्षी सुरक्षा आदेश को कार्यान्वित करने का दायित्व है। धमकी की आशंका के अनुसार वह सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा। पुलिस अपर आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/पुलिस अपर आयुक्त प्रकोष्ठ के प्रधान होंगे।
3. **धमकी के अनुसार साक्षियों का वर्गीकरण:**
- संवर्ग "क" : जहां खतरा साक्षी के जीवन या उसके परिवार के सदस्य को हो और मुकदमों की जांच/परीक्षण के दौरान या उसके बाद वास्तविक अवधि के लिए उसका सामान्य जीवन प्रभावित होता हो।
- संवर्ग "ख" : जहां केवल जांच प्रक्रिया या परीक्षण के दौरान खतरा साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति तक हो।
- संवर्ग "ग" : जहां खतरा मामूली हो और जांच प्रक्रिया के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा धमकाने तक हो।
4. **साक्षी सुरक्षा निधि:**
- (क) साक्षी सुरक्षा निधि नामक एक निधि होगी जिसमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए खर्च का वहन किया जाएगा।
- (ख) साक्षी सुरक्षा निधि में निम्न सम्मिलित होंगे:-
- सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किए गए बजट आबंटन;
 - संहिता की धारा 357 के अंतर्गत लगाए गए अर्थदंड की राशि की प्राप्ति तथा साक्षी संरक्षक निधि में न्यायालय द्वारा जमा कराए जाने के आदेश किये हों;
 - अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/लोकोपकारी/परोपकारी संस्थाओं/संगठनों तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान/वंदा/अंशदान।
- (ग) इस निधि का संचालन मंडल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।
5. **सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना:-** इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा चाहने वाले को क्षेत्राधिकार के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
6. **आवेदन पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया:-**
- (क) जैसे ही निर्धारित फार्म में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होता है वह पुलिस के अपर आयुक्त/पुलिस के उपायुक्त/जिला के पुलिस अपर उपायुक्त/मामले की जांच करने वाले यूनिट से धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश पारित करेगा।
- (ख) मामले में धमकी की सन्निकटता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अंतरिम सुरक्षा के लिए आदेश पारित कर सकती है।
- (ग) पुलिस अपर आयुक्त/पुलिस के उपायुक्त/जिला के पुलिस अपर उपायुक्त/मामले की जांच करने वाली यूनिट द्वारा अविलम्ब धमकी विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और यह ऑर्डर की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के अंदर सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए।
- (घ) पुलिस अपर आयुक्त/पुलिस के उपायुक्त/जिला के पुलिस अपर उपायुक्त/मामले की जांच करने वाली यूनिट रिपोर्ट में धमकी का वर्गीकरण करेंगे और साक्षियों या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुझावात्मक उपाय भी प्रस्तुत करेंगे।

- (ड) साक्षी सुरक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान सक्षम प्राधिकारी गवाहों तथा/या उसके परिवार के सदस्यों/कर्मचारियों या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति से भी संपर्क कर सकता है ताकि साक्षी की सुरक्षा/आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके।
- (घ) साक्षी सुरक्षा आवेदन पर सभी सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के बंद कक्ष में कैमरे के सामने होगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा।
- (छ) आवेदन के दायर होने के सात कार्य दिवसों के अंदर निपटा लिया जाएगा।
- (ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी सुरक्षा आदेश को साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सभी साक्षी सुरक्षा आदेशों के कार्यान्वयन की संपूर्ण जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के आयुक्त की है तथापि पहचान अथवा/और पुनःस्थान निर्धारण परिवर्तन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्ष्य/साक्षी संरक्षण आदेश मंडल आयुक्त, दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- (झ) किसी साक्षी संरक्षण आदेश पारित होने पर साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामले की जांच कर रहे जिला/युनिट के अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/अपर उपायुक्त पुलिस के साथ प्रत्येक मामले में परामर्श करके मासिक अनुवर्ती प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

7. संरक्षण के प्रकार:—

साक्षी संरक्षण उपायों के आदेश धमकी की गंभीरता तथा सीमित समय सीमा के लिये होंगे। इनमें निम्न हो सकते हैं:—

- (क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और दोषी जांच अथवा मुकदमे/परीक्षण के दौरान आमने सामने न आए;
- (ख) डाक और टेलिफोन कॉलों पर नजर रखना;
- (ग) साक्षी का टेलिफोन नम्बर परिवर्तन करने के लिए टेलिफोन कंपनी के साथ प्रबंध करना या उसे कोई सूचीबद्ध टेलिफोन नम्बर न देना;
- (घ) साक्षी के घर में सुरक्षा यंत्र लगाना जैसे सुरक्षा दरवाजे, सीसीटीवी, अलार्म, बाड़ आदि लगाना ;
- (ड) परिवर्तित नाम या अक्षर के साथ सम्बोधित करके साक्षी की पहचान छिपाना;
- (घ) साक्षी के लिये आपातकालिक स्थिति में संपर्क व्यक्ति;
- (छ) गुप्त सुरक्षा व्यवस्था करना साक्षी के घर के आसपास नियमित गश्त लगाना;
- (ज) किसी परिजन के घर में ठहराना या किसी निकटवर्ती करबे में परिवर्तन करना;
- (झ) न्यायालय में जाने या आने के लिये मार्गरक्षा और सुनवाई की तिथि के लिये सरकारी वाहन या राज्य वित्त पोषित वाहन की व्यवस्था करना;
- (ञ) बंद कमरे में परीक्षण करना/मुकदमा चलाना;
- (ट) बयान तथा गवाही अभिलेखबद्ध करते समय किसी सहयोगी को साथ रहने की अनुमति देना;
- (ठ) विशेष रूप से अभिकल्पित अतिसंवेदनशील न्यायालय कक्षों का प्रयोग, जिनमें सीधे संबंध रखने, साक्षियों और दोषियों के लिये अलग-अलग रास्ते रखने के अतिरिक्त वन वे दर्पण एवं स्क्रीन हों जिसमें साक्षी के मुंह का बिम्ब बदलने तथा साक्षी की वाणी का आडियोफीड बदलने का विकल्प खुला हो, ताकि उसकी पहचान न हो सके;
- (ड) बाधाओं के बिना दिन प्रति दिन आधार पर परीक्षण के दौरान साक्ष्य का तीव्र अभिलेखन सुनिश्चित करना;
- (ढ) यदि वांछित हो, तो पुनः स्थान निर्धारण, नया व्यवसाय/कारोबार बनाए रखने या प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ साक्षी संरक्षण निधि से साक्षी को समय-समय पर आवधिक वित्तीय सहायता/अनुदान देना; तथा
- (ण) सुरक्षा, उपायों का कोई अन्य रूप, जो विशेष रूप से साक्षी द्वारा मांगे गए हैं।

8. निगरानी और पुनर्विचार

एक बार संरक्षण आदेश पारित हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी इस पर नजर रखेगा और मामले में प्राप्त अनुवर्ती प्रतिवेदनों की बातों पर पुनर्विचार कर सकता है।

9. पहचान का संरक्षण

किसी घोर अपराध की जांच या परीक्षण के दौरान पहचान संरक्षण की मांग संबंधी आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी धमकी की आशंका संबंधी विश्लेषण प्रतिवेदन मांगेगा और साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की यह पता लगाने के लिए उचित जांच करेगा कि क्या पहचान संरक्षण आदेश पारित करने की आवश्यकता है या नहीं।

आवेदन की सुनवाई के दौरान साक्षी की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी, जिससे साक्षी की पहचान पता लगने की संभावना है। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध विषयवस्तु के आधार आवेदन पत्र का निपटान कर सकता है।

यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी पहचान छिपाने का आदेश एक बार पारित हो जाता है, तो मंडलायुक्त, दिल्ली सरकार के साक्षी संरक्षण प्रकाष्ठ का यह सुनिश्चित करने दायित्व होगा कि ऐसे साक्षी की पहचान पूर्णतः संरक्षित रखी गई है।

सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के अधीन जब तक किसी साक्षी की पहचान सुरक्षित रखी गई है तब तक साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों का विवरण देगा जिनके साथ किसी आपातक स्थिति में साक्षी द्वारा संपर्क किया जा सकेगा।

10. योजना के बारे में साक्षियों को अवगत करना:

जांच अधिकारी/न्यायालय को "साक्षी संरक्षण योजना" के अस्तित्व तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में प्रत्येक साक्षी को बताना आवश्यक होगा।

11. अभिलेख की गोपनीयता एवं संरक्षण:

सक्षम प्राधिकारी, मंडलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ कक्ष के अधिकारी, थानाध्यक्ष, जांच अधिकारी और सभी अन्य संबंधित कर्मचारी, जिसमें दोनों पक्षकारों के वकील शामिल हैं। वे पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय यह भी किसी लिखित आदेश के बिना और इस योजना के अन्तर्गत कोई भी अभिलेख प्रलेख या कार्यवाही से संबंधित सूचना का किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ लेनदेन नहीं करेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाहियों से संबंधित सारे अभिलेख की तब तक संभाल की जाएगी जब तक किसी विधि न्यायालय के समक्ष संबंधित मुकदमा या इसकी अपील लम्बित है। अन्तिम न्यायालयी कार्यवाहियों के निपटान के तीन वर्ष बाद अभिलेख की स्कैन की गई सॉफ्ट प्रतियों को संभालने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेख की हार्ड प्रती की छंटाई की जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त-सचिव (गृह)

दिल्ली साक्षी संरक्षण योजना 2015 के अन्तर्गत साक्षी संरक्षण आवेदन पत्र

(दो प्रतियों में भरा जाये)

सेवा में,

सक्षम अधिकारी
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पटियाला हाउस न्यायालय, दिल्ली।

1	साक्षी का विवरण (साफ अक्षरों में भरिए) 1 नाम 2 आयु 3 पिता का नाम 4 आवासीय पता 5 क्या साक्षी पहचान संरक्षण आदेश चाहता है यदि हां, तो कारण बतायइये। 6 परिवार के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण जिन्हें घगकियां मिल रही है। 7 क्या साक्षी स्थान परिवर्तन का इच्छुक है, यदि हां, तो स्थान सुझाए और इसकी पद्धति	
2	अपराधिक विषयवस्तु का विवरण 1 प्राथमिकी संख्या 2 धारा 3 थाना 4 जगपद 5 डी डी संख्या (यदि प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है)	

3	दोषी/अपराधी का विवरण 1 नाम 2 पता	
4	घमकियां देने वाले व्यक्ति या सदेहारपद व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण	
5	घमकी का स्वरूप, मामले के संबंध में प्राप्त घमकी का संक्षिप्त विवरण दीजिए, जिसमें तिथि, स्थान, पद्धति/साधन और प्रयुक्त शब्दों का विवरण हो	
6	साक्षी द्वारा/के लिये मांगे गए साक्षी संरक्षण उपायों की प्रकृति	
7	यदि आवश्यक हो तो अन्तरिम/अविलम्बनीय साक्षी सुरक्षा आवश्यकताओं का विवरण दीजिए	

साक्षी को अपने हस्ताक्षर से एक अलग प्रतिज्ञा प्रस्तुत करनी होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी/गंडलायुक्त दिल्ली सरकार/साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का पूरा सहयोग करेगा/करेगी।

आवेदक/साक्षी अतिरिक्त जानकारी देने के लिये अतिरिक्त शीट का प्रयोग कर सकेगा।

आवेदक का पूरा नाम
हस्ताक्षर सहित

दिनांक

स्थान

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2015

No.F.11/79/2013/HP-II-6651.—In pursuance of Delhi High Court's judgment dated 22.05.2013 in Criminal Appeal No.193/2006 *State Vs. Manu Sharma & Others*, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Scheme for Protection of Witnesses in Delhi while taking a holistic approach to witness protection needs.

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**

- This Scheme shall be called "**Delhi Witness Protection Scheme, 2015**".
- It shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi (within the jurisdiction of Government of NCT of Delhi)
- It shall come into force from the date of its publications in the Delhi Gazette.

2. **DEFINITIONS:**

- "**Code**" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- "**Concealment of Identity of Witness**" means and includes any condition prohibiting publication or revealing, in any manner, directly or indirectly, of the name, address and other particulars which may lead to the identification of the witness;
- "**Competent Authority**" means Member Secretary/Officer on Special Duty, Delhi State Legal Services Authority who alone can pass directions for witness protection under this Scheme and who may also issue

orders for protection of identity/change of identity/relocation of a witness, categorization of threat, duration and types of protection as detailed in clause 7;

- (d) **"Family Member"** includes parents, spouse, siblings, children, grand children of the witness;
- (e) **"Form"** means "Witness Protection Application Form" appended to this Scheme;
- (f) **"Government"** means the Government of National Capital Territory of Delhi;
- (g) **"In Camera Proceedings"** means proceedings wherein the public and press are not allowed to participate;
- (h) **"Live Link"** means and include a live television link or other such arrangement whereby a witness, while absent from the courtroom can depose in the matter;
- (i) **"Protection Measures"** means action taken by the Court taking evidence during the testimony to ensure that witnesses may testify free of intimidation or fear for their and their family members life or reputation or property; such measures include, but are not limited to, videoconferencing, avoiding face to face contact between witness and the accused and withholding of details of a witness's identity;
- (j) **"Serious Offences"** mean those offences which are punishable with death or life imprisonment or an imprisonment of a duration not less than seven years;
- (k) **"State Legal Services Authority"** means the Delhi State Legal Services Authority and as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);
- (l) **"Threat Analysis Report"** means a detailed report prepared and submitted by the Additional Commissioner of Police /Deputy Commissioner of Police /Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Unit investigating the case qua the seriousness and credibility of the threat perception to the witness or his family members. It shall contain specific details about the nature of threats faced by the witness or his family to their life, reputation or property apart from analyzing the extent, the person or persons making the threat, have the intent, motive and resources to implement the threats.
It shall also categorize the threat perception apart from suggesting the specific witness protection steps which deserve to be taken in the matter;
- (m) **"Witness"** means any person, who possesses information or document about any crime, which is regarded by the competent authority as being material to any Criminal proceedings and who has made a statement, or who has given or agreed to give evidence in relation to such proceedings;
- (n) **"Witness Protection Application"** means an application moved in the prescribed form before the Competent Authority for seeking a Witness Protection Order. It can be moved by the witness, his family member or his duly engaged counsel or Investigating Officer / Station House Officer concerned and the same should preferably be got forwarded through the Prosecutor concerned;
- (o) **"Witness Protection Fund"** means the fund created for bearing the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority under this Scheme;
- (p) **"Witness Protection Order"** means an order passed by the Competent Authority detailing the steps to be taken for ensuring the safety of witness from threats to his or his family member's life, reputation or property. It also includes interim order, if any passed, during the pendency of Witness Protection Application;
- (q) **"Witness Protection Cell"** means a dedicated Cell of Delhi Police assigned the duty to implement the witness protection order. It shall be responsible for the security as per threat perception. The Cell shall be headed by the Additional Commissioner of Police /Deputy Commissioner of Police /Additional Deputy Commissioner of Police.

3. CATEGORIES OF WITNESS AS PER THREAT PERCEPTION:

- Category 'A' :** Where the threat extends to life of witness or his family members and their normal way of living is affected for a substantial period, during investigation/trial or even thereafter.
- Category 'B' :** Where the threat extends to safety, reputation or property of the witness or his family members, only during the investigation process or trial.
- Category 'C' :** Where the threat is moderate and extends to harassment and intimidation of the witness or his family member's, reputation or property, during the investigation process.

4. WITNESS PROTECTION FUND :

- (a) There shall be a Fund, namely, the Witness Protection Fund from which the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority, shall be met.
- (b) The Witness Protection Fund shall comprise the following:-

- (i) Budgetary allocation made in the Annual Budget by the Government;
 - (ii) Receipt of amount of fines imposed under section 357 of the Code and ordered to be deposited by the courts in the Witness Protection Fund;
 - (iii) Donations/contributions from International /National/ Philanthropist/ Charitable Institutions/ Organizations and individuals.
- (c) The said Fund shall be operated by the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. FILING OF APPLICATION BEFORE THE COMPETENT AUTHORITY:

The application for seeking protection order under this scheme can be filed in the prescribed form before the Competent Authority as per area jurisdiction along with supporting documents, if any, in duplicate.

6. PROCEDURE FOR PROCESSING THE APPLICATION:

- (a) As and when an application is received by the Competent Authority, in the prescribed form, it shall forthwith pass an order for calling the Threat Analysis Report from the Additional Commissioner of Police/Deputy Commissioner of Police /Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Unit investigating the case.
- (b) Depending upon the urgency in the matter owing to imminent threat, the Competent Authority can pass orders for interim protection of the witness or his family members.
- (c) The Threat Analysis Report shall be prepared expeditiously by the Additional Commissioner of Police/Deputy Commissioner of Police /Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Unit investigating the case while maintaining full confidentiality and it shall reach the Competent Authority within five working days of receipt of the order.
- (d) In the report, the Additional Commissioner of Police/Deputy Commissioner of Police /Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Unit investigating the case shall categorize the threat perception and shall also submit the suggestive measures for providing adequate protection to the witness or his family.
- (e) While processing the application for witness protection, the Competent Authority shall also interact with the witness and/or his family members/employers or any other person deemed fit so as to ascertain the witness protection needs of the witness.
- (f) All the hearings on Witness Protection Application shall be held *in-camera* in the chamber of the Competent Authority while maintaining full confidentiality.
- (g) An application shall be disposed of within seven working days of its filing.
- (h) The Witness Protection Order passed by the Competent Authority shall be implemented by the Witness Protection Cell. Overall responsibility of implementation of all witness protection orders passed by the Competent Authority shall lie on the Commissioner of Police, Delhi;

However the Witness Protection Order passed by the Competent Authority for change of identity or/and relocation shall be implemented by the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

- (i) Upon passing of a Witness Protection Order, the Witness Protection Cell shall file a monthly follow-up report before the Competent Authority, in each case in consultation with the Additional Commissioner of Police/Deputy Commissioner of Police/Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Unit investigating the case.

7. TYPES OF PROTECTION:

The witness protection measures ordered shall be proportional to the threat and for limited duration. They may include:

- (a) Ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation or trial;
- (b) Monitoring of mail and telephone calls;
- (c) Arrangement with the telephone company to change the witness's telephone number or assign him or her an unlisted telephone number;
- (d) Installation of security devices in the witness's home such as security doors, CCTVs, alarms, fencing etc;
- (e) Concealment of identity of the witness by referring to him/her with the changed name or alphabet;
- (f) Emergency contact persons for the witness;

- (g) Close protection, regular patrolling around the witness's house;
- (h) Temporary change of residence to a relative's house or a nearby town;
- (i) Escort to and from the court and provision of Government vehicle or a State funded conveyance for the date of hearing;
- (j) Holding of *in-camera* trials;
- (k) Allowing a support person to remain present during recording of statement and deposition;
- (l) Usage of specially designed vulnerable witness court rooms which have special arrangements like live links, one way mirrors and screens apart from separate passages for witnesses and accused, with option to modify the image of face of the witness and to modify the audio feed of the witness' voice, so that he/she is not identifiable;
- (m) Ensuring expeditious recording of deposition during trial on day to day basis without adjournments;
- (n) Awarding time to time periodical financial aids/grants to the witness from Witness Protection Fund for the purpose of re-location, sustenance or starting new vocation/profession, if desired;
- (o) Any other form of protection measures considered necessary, and specifically, those requested by the witness.

8. MONITORING AND REVIEW:

Once the protection order is passed, the Competent Authority would monitor its implementation and can review the same in terms of follow-up reports received in the matter.

9. PROTECTION OF IDENTITY :

During the course of investigation or trial of any serious offence, an application for seeking identity protection can be filed in the prescribed form before the Competent Authority.

Upon receipt of the application, the Competent Authority shall call for the Threat Analysis Report and shall examine the witness or his family members or any other person it deem fit to ascertain whether there is necessity to pass an identity protection order.

During the course of hearing of the application, the identity of the witness shall not be revealed to any other person, which is likely to lead to the witness identification. The Competent Authority can thereafter dispose of the application as per material available on record.

Once, an order for concealment of identity of witness is passed by the Competent Authority, it shall be responsibility of Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi/Witness Protection Cell to ensure that identity of such witness is fully protected.

As long as identity of any witness is protected under an order of the Competent Authority, the Witness Protection Cell shall provide details of persons who can be contacted by the witness in case of emergency.

10. WITNESSES TO BE APPRISED OF THE SCHEME:

It shall be mandatory for Investigating Officer/Court to inform each and every witness about the existence of "Witness Protection Scheme" and its salient features.

11. CONFIDENTIALITY AND PRESERVATION OF RECORDS:

The Competent Authority, Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, Witness Protection Cell's officials, Station House Officer, Investigating Officer and all other concerned officials including Lawyers from both sides shall maintain full confidentiality and shall ensure that under no circumstance, any record, document or information qua the proceedings under this scheme shall be shared with any person in any manner except with the Trial Court/Appellate Court and that to on a written order.

All the records pertaining to proceedings under this scheme shall be preserved till such time the related trial or appeal thereof is pending before a Court of Law. After three years of disposal of the last Court proceedings, the hard copy of the records can be weeded out by the Competent Authority after preserving the scanned soft copies of the same.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

O.P.MISHRA, Addl. Secy. (Home)

Witness Protection Application Form*under***Delhi Witness Protection Scheme, 2015**

Before,

(To be filed in duplicate)

The Competent Authority,
Delhi State Legal Services Authority,
Patiala House Courts,
Delhi.

1.	Particulars of the Witness (Fill in Capital): 1) Name 2) Age 3) Father's Name 4) Residential Address 5) Is witness desirous of Identity protection order, if yes, give reasons 6) Name and other details of family members of the witness who are receiving or perceiving threats 7) Is witness desirous of relocation, if yes, please suggest the place and manner of it.	
2.	Particulars of Criminal matter: 1) FIR No. 2) Under Section 3) Police Station 4) District 5) D.D. No. (in case FIR not yet registered)	
3.	Particulars of the Accused: 1) Name 2) Address	
4.	Name and other particulars of the person giving/suspected of giving threats	
5.	Nature of threat perception. Please give brief details of threat received or perceived in the matter with specific date, place, mode and words used	
6.	Nature of witness protection measures prayed by/for the witness	
7.	Details of Interim urgent Witness Protection needs, if required	

- Witness shall file a separate undertaking under his/her signature that he/she shall fully co-operate with the Competent Authority and Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi/Witness Protection Cell.
- Applicant/witness can use extra sheets for giving additional information.

Date:

(Full Name with signature)

Place: